अमेरिका-भारत सीईओ फोरम

अमेरिका और भारत के 20 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के समूह ने "अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी" पर एक रिपोर्ट नई दिल्ली में 2 मार्च को राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसमें अमेरिका-भारत स्थायी फोरम बनाने का आग्रह किया गया है जिसे दोनों देशों के बीच व्यापार भागीदारी बढ़ाने का खाका विकसित करने का जिम्मा सौंपा जाए।

दोनों देशों के बीच व्यापार 20 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है। उद्योग जगत के अग्रणी लोगों का यह सर्वसम्मत रुख है कि "नई आर्थिक भागीदारी" से दोनों देशों में व्यापार और निवेश गतिविधियां बढ़ाने और माल और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच में वृद्धि के काफी अवसर मिलेंगे। साथ ही, दोनों देशों को अपनी-अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा प्रतियोगी होने के अवसर मिलेंगे।

सीईओ समूह ने दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए छह क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर पहचान की है जिन पर सरकार और उद्योग जगत की भागीदारी के लिए ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार, "इन क्षेत्रों का आर्थिक सहयोग के लिहाज से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये कई और क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।" प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:

- सेवा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की स्वतंत्रता, लोगों की मुक्त आवाजाही, शुल्कों में कटौती के जरिये व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा।
- भारत में मूलभूत सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए अमेरिकी निवेश के जरिये 5 अरब डॉलर का कोष बनाना जिसमें भारत सरकार की भागीदारी अल्प मात्रा में हो।
- कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और शोध एवं विकास केंद्रों की स्थापना के जरिये प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- कार्यकुशलता विकसित करने में भागीदारी।
- उत्पाद डिजाइन एवं विकास के लिए औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र शुरू करना।
- विवाद निपटारे का तंत्र स्थापित करना।

इसके अलावा फोरम ने 15 व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेष कार्ययोजना की सिफारिश की है। दोनों देशों की सरकारों द्वारा नीतियों में बदलाव के बाद इससे व्यापार एवं निवेश में बढ़ोतरी की बहुत गुंजाइश है। फोरम ने 30 अन्य क्षेत्रों में 'सकारात्मक माहौल' बनाने का जोरदार पक्ष लिया है जिससे कि एक तय समय में सभी उत्पादों, कृषि एवं मैनुफैक्चरिंग में गति तथा क्षमता बढ़े और पारदर्शिता आए। □

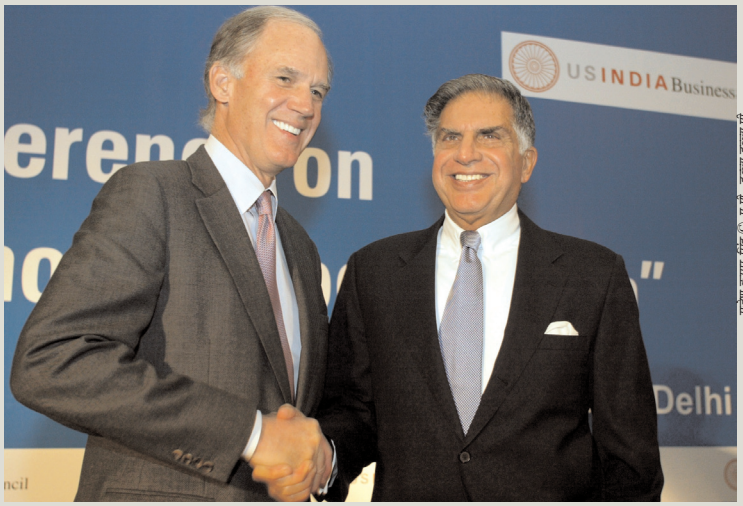

विलियम बी. हैरिसन, जूनियर और रतन टाटा: अमेरिका-भारत सीईओ फोरम के सह-अध्यक्ष।

राकेश कुमार सिंह © ए. पी.-डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.

अमेरिकी सदस्य	भारतीय सदस्य
विलियम बी. हैरिसन, जूनियर, जेपी मोर्गन चेज, सह-अध्यक्ष	रतन टाटा, टाटा संस लिमिटेड, सह-अध्यक्ष
पॉल हैनराहन, ए.ई.एस. कार्पोरेशन	डॉ. प्रताप सी. रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल्स
वारेन आर. स्टाले, करगिल इंकॉर्पोरेटेड	बाबा कल्याणी, भारत फोर्ज लिमिटेड
चार्ल्स ओ. प्रिंस, सिटी ग्रुप	किरण मजूमदार शॉ, बायोकोन लिमिटेड
डेविड एम. कोटे, हनीवैल इंका.	दीपक पारेख, एचडीएफसी एंड आईडीएफसी
हैरोल्ड मैक्ग्रा, द मैक्ग्राहिल कंपनीज	अशोक गांगुली, आईसीआईसीआई वन सोर्स लिमिटेड
थॉमस जे. ओनील, पारसंस ब्रिकरहाफ इंका.	नंदन नीलकेनी, इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
स्टीवन रेनेमंड, पेप्सिको	योगी देवेश्वर, आईटीसी लिमिटेड
क्रिस्टोफर रॉड्रिगस, वीजा इंटरनेशनल	अनलजीत सिंह, मैक्स इंडिया लिमिटेड
ऐन.एम. मल्काही, जीरॉक्स इंका.	मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

चारु धारीवाल © ए. पी.-डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.

भविष्य के कारोबारी दिग्गजों से मुलाकात

राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) में सवाल-जवाब के दौरान 400 छात्रों, अध्यापकों और युवा उद्यमियों से कहा, "किसी देश के बारे में आप वहां के युवाओं की तेजस्विता से जान सकते हैं। आज मैं भविष्य के सीईओ से मिल रहा हूं। वे लोग जो भारत की आर्थिक समृद्धि के महान इंजन को चलाने में मदद करेंगे- दुनिया की बेहतरी के लिए, मैं इसे इसी तरह देखता हूं।"

उद्योग जगत के अग्रणी लोगों, उद्यमियों और शिक्षाविदों ने एशिया में अग्रणी व्यावसायिक एवं प्रबंधन शिक्षा संस्थान बनाने का सपना देखा और इंडियन बिजनेस स्कूल की स्थापना की। ये लोग इसके संचालन मंडल में भी हैं। यह संस्थान अमेरिका के बिजनेस स्कूल की तर्ज पर स्थापित किया गया है और यह एक साल की एमबीए डिग्री देता है। इसका इलिनोइस की नॉर्थ-वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलोग प्रबंधन संस्थान, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल और लंदन बिजनेस स्कूल से तालमेल है। यहां अमेरिकी छात्र भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आते हैं।

राष्ट्रपति बुश ने 16 युवा भारतीय उद्यमियों से बातचीत की जिनमें कुछ ऐसे थे जो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़े थे और फिर कारोबार शुरू करने के लिए भारत आ गए। राष्ट्रपति ने इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाने की जरूरत (जिससे कि भारतीय किसान अपने माल को बाजार तक पहुंचा सकें), शिक्षा, कर नीति सुधार, निर्यात नियंत्रण और निवेश नियमों में पारदर्शिता पर बातचीत की।

राष्ट्रपति ने कहा, "यह अमेरिका के हित में है... कि भारत के साथ मुक्त और सही तरीके से व्यापार हो। यह अमेरिका के हित में है कि इस महान देश में उद्यमी वर्ग को बढ़ावा मिले। यह भारत के हित में है कि इस देश में उद्यमी वर्ग आगे बढ़े जिससे कि लोग अपने सपने साकार कर सकें।" राष्ट्रपति के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आने की उनकी इच्छा के पीछे एक कारण यह है कि "यह नया संस्थान है जो नए तरीकों का इस्तेमाल लोगों की सफलता के नए औजार मुहैया कराने में कर रहा है।" □